



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1941 (श10)

(सं० पटना 1270) पटना, वृहस्पतिवार, 21 नवम्बर 2019

सं० 08/नि०था०-11-04/2017-सा०प्र०-14097
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

16 अक्टूबर 2019

श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-714/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलनों से संबंधित दर्ज रफीगंज (औरंगाबाद) थाना कांड संख्या-229/2012 दिनांक 12.12.2012 (अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियंत्रित कांड) में अनुसंधानोपरांत उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं दिनांक 28.11.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी सूचना अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1741 दिनांक 13.12.2017 एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 2406 दिनांक 11.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-463 दिनांक 09.01.2018 द्वारा श्री सिंह को गिरफ्तारी की तिथि (दिनांक 28.11.2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4296 दिनांक 04.09.2018 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विषयांकित मामले से संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इस बीच विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16231 दिनांक 12.12.2018 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 16540 दिनांक 19.12.2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (पत्रांक-00 दिनांक 02.04.2019) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा आरोपवार स्थिति स्पष्ट करते हुए आरोपों को निराधार बताया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 8020 दिनांक 14.06.2019 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4285 दिनांक 11.09.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

4. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी।

5. अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-714/2011), के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों तहत कराने का निर्णय लिया गया। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

6. श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1270-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>